बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 138 ● नई दिल्ली ● शनिवार 14 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका केस की जांच में देरी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, जमानत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के मामले में आप नेता नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। अदालत ने पुलिस से पूछा कि अभी तक आगे की जांच पूरी क्यों नहीं हुई और इसमें देरी क्यों हो रही है? इस दौरान अदालत ने बाल्यान की जमानत याचिका पर जिरह सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को नरेश बाल्यान ने चुनौती दी है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच चौथी बार हुई जयशंकर-अराघची की बातचीत, होर्मुज से मिल रही अछी खबर

नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची से बात की। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह दोनों नेताओं की चौथी बातचीत थी। जयशंकर और अराघची के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच बीती रात फोन पर बातचीत हुई। बीती 28 फरवरी को जब अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, उसके बाद भी जयशंकर ने अराघची से बात की थी।

पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच बीती 5 मार्च और फिर 10 मार्च को भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। बीते करीब 15 दिनों में दोनों के बीच गुरुवार रात को चौथी बार बात हुई है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, कल रात ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ एक और बातचीत हुई। इस बातचीत में द्विपक्षीय मामलों के

साथ-साथ ब्रिक्स से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत, होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक शिपिंग मार्ग से भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इस्राइल के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद तेहरान ने इस मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हालांकि गुरुवार को एक अछी खबर सामने आई कि एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत पहुंचा। इसे भारत के कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है। ईरान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अराघची ने अपने भारतीय समकक्ष को अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए हमलों से पैदा हुई स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा पर इसके परिणामों के बारे में जानकारी दी। ईरानी विदेश मंत्री ने जयशंकर के सामने आत्मरक्षा के वैध अधिकार के इस्तेमाल के तेहरान के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया। बयान में कहा गया, अराघची ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों और संगठनों द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण की निंदा किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने के एक मंच के रूप में ब्रिक्स की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने मौजूदा समय में क्षेत्र और दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने में ब्रिक्स की अहम भूमिका पर जोर दिया।

जलभराव से मिलेगी निजात, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं, मिशन मोड में नालों की सफाई का काम

नई दिल्ली । दिल्ली में यमुना को स्वछ और निर्मल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. हाईटेक मशीनों के जरिए ड्रेनों की सफाई का काम किया जा रहा है. नई-नई मशीनें इस काम के लिए उतारी गई हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में ड्रेनों की सफाई का काम अब मिशन मोड में किया जा रहा है. शुक्रवार (13 मार्च) को बदुसराय पुल और पंखा रोड ड्रेन में आधुनिक लॉन्ग और शॉर्ट बूम का इस्तेमाल शुरू किया गया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, ये हाई-टेक मशीनें ड्रेनों और जलाशयों में जमी सिल्ट, कचरा और जलकुंभी को तेजी से हटाने में सक्षम हैं, जिससे सफाई का काम पहले से यादा तेज और प्रभावी होगा. इससे पानी का बहाव बेहतर होगा, ड्रेनों की सफाई तेज होगी और जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी. यमुना को स्वछ और निर्मल बनाने के लिए दिल्ली में ड्रेनों की सफाई का काम मिशन मोड में चल रहा है। इसी कड़ी में आज बड़ुसराय पुल और पंखा रोड ड्रेन में नई लॉन्ग और शॉर्ट बूम का इस्तेमाल शुरू किया गया है। ड्रेनों और जलाशयों में जमी सिल्ट और कचरा निकाले जाने का काम तेजी से किए जाने के बाद आसपास के इलाकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आशीष सूद समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनवरी महीने में ही यमुना को फिर से स्वछ और प्रवाहमान बनाने के लिए मिशन-मोड में ठोस एक्शन प्लान लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी. इस दौरान यमुना की मौजूदा हालत, सीवेज ट्रीटमेंट, नालों की सफाई और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने जैसे कामों की समीक्षा की गई थी.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि यमुना केवल नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवनरेखा है

डीटीसी बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर, पिंक सहेली कार्ड के बिना भी मिलेगी यह सुविधा

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाएं नया पिंक कार्ड मिलने तक पिंक टिकटों का उपयोग करके डीटीसी बसों में यात्रा करना जारी रख सकती हैं. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने एक बयान में दिल्ली की महिलाओं से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लेने के लिए परेशान न होने या जल्दबाजी न करने का आग्रह किया है. बयान में कहा गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपने पास 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' उपलब्ध न होने के बावजूद मौजूदा प्रणाली के अनुसार 'पिंक पेपर टिकट' का उपयोग करके डीटीसी बसों में यात्रा करना जारी रख सकती हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि यह आकलन करने के बाद कि अधिकतर पात्र महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मिल चुके हैं, और दिल्ली सरकार धीरे-धीरे कागजी टिकट प्रणाली को समाप्त करके पूरी तरह कार्ड आधारित प्रणाली लागू करेगी. डीटीसी ने कहा, महिला यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे परेशान न हों या जल्दबाजी न करें, क्योंकि कार्ड वितरण समय के साथ सुचारू रूप से जारी रहेगा और सभी पात्र महिलाएं आसानी से अपना कार्ड प्राप्त कर सकेंगी.

दिल्ली की पात्र महिलाएं राष्ट्रीय राजधानी में डीटीसी द्वारा स्थापित 50 नामित काउंटरों से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' निशुल्क प्राप्त कर सकती हैं. दिल्ली सरकार ने दो मार्च को 'पिंक सहेली कार्ड' पहल शुरू की, जिसने केंद्र की एक राष्ट्र, एक कार्ड पहल के तहत पहले से चली आ रही 'पिंक पेपर प्रणाली' को 'पिंक एनसीएमसी कार्ड' के माध्यम से प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे मुफ्त यात्रा केवल दिल्ली निवासियों तक ही सीमित हो गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि इस कार्ड से दिल्ली-निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का सुगम सशुल्क उपयोग संभव हो सकेगा.

पीरियड्स में पेड लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सीजेआई बोले- कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाली एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के लाभ को अनिवार्य बनाने से अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है और नियोक्ताओं को महिलाओं को नौकरी पर रखने से रोका जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस अनुरोध का महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता की दलील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, ये दलीलें भय पैदा करने, महिलाओं को हीन बताने और यह जताने के लिए दी जा रही हैं कि मासिक धर्म उनके लिए कोई बुरी

घटना है। यह एक सकारात्मक अधिकार है।

लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए जिसे सवैतनिक अवकाश देना पड़ता है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि मासिक धर्म अवकाश एक वैध मुद्दे को स्वीकार करता है, लेकिन इसे कानून के माध्यम से अनिवार्य बनाना सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रतिकूल हो सकता है। यह जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जिनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने बताया कि कुछ राज्यों और निजी संगठनों ने पहले ही मासिक धर्म अवकाश लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केरल ने छात्रों को छूट दी है और कई कंपनियों ने स्वेच्छा से ऐसा अवकाश प्रदान किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वैच्छिक उपाय स्वागत योग्य हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी बाध्यता के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रूप से दिया गया अवकाश उत्कृष्ट है। जिस क्षण आप इसे कानून में अनिवार्य कर देंगे, कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। कोई भी उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरी में नहीं लेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण वह परमादेश जारी करने के लिए इछुक नहीं है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को सभी हितधारकों से परामर्श करके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। तदनुसार, जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया।

बल चोर अरेस्ट- दिल्ली मेट्रो की नई लाइन से 1000 मीटर वायर हुई थी गायब

दिल्ली । दिल्ली मेट्रो के मजलिस पार्क और भलस्वा मेट्रो स्टेशनों से सिग्नलिंग केबल चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस चोरी के कारण मेट्रो का सिग्नलिंग सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ और सेवाएं बाधित हुईं। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 170 से 180 मीटर जली हुई केबल बरामद की है, जबकि कुल 1000 मीटर केबल चोरी होने का अनुमान है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बीती 12 मार्च की सुबह करीब 4:20 बजे डीएमआरसी के ओसीसी/एमबी सिग्नल कंट्रोलर एमआरएस मजलिस पार्क से सिग्नलिंग केबल चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही रात्रि गश्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने पास के जंगल में कुछ लोगों को तांबे के लिए तार पिघलाते देखा। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जहांगीरपुरी, दिल्ली निवासी शेख शफीक के रूप में हुई है। आजादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और डीएमआरसी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता जसबीर सिंह, एएसई/सिग/एल-8 एक्सटेंशन, एमआरएस मजलिस पार्क ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लगभग 1000 मीटर सिग्नलिंग केबल गायब पाई गई। पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और आगे की जांच जारी है। मेट्रो पुलिस और डीएमआरसी की टीम ने संवेदनशील स्थानों का संयुक्त सर्वेक्षण भी किया है। जिस मेट्रो की नई लाइन पर चोरी हुई है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को दिल्ली मेट्रो के दो कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसमें से एक कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी थी। इसमें दो नए मेट्रो रेल कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है।

दिल्ली में हज यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज, 18 अप्रैल से होगी शुरुआत

नई दिल्ली । हज 2026 की पवित्र यात्रा को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं. दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकाल को छह माह का विस्तार मिलने के बाद 12 मार्च को विस्तारित कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें हज यात्रियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही रामलीला मैदान में हज कैंप की तैयारियों का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया.

छह माह के विस्तार के बाद हुई पहली अहम बैठक

दिल्ली सरकार के 9 मार्च को जारी राजपत्र (असाधारण) के माध्यम से दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकाल को आगामी छह माह के लिए बढ़ाया गया है. इसी विस्तार के बाद 12 मार्च को विस्तारित हज कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें हज 2026 की तैयारियों को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया. इस बैठक में हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, मेंबर नाजिया दानिश (निगम पार्षद), मेंबर मोहम्मद साद, हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी और उप कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली ने भाग लिया. बैठक के दौरान हज यात्रियों की सुविधा, प्रस्थान व्यवस्था और

कैंप संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

रामलीला मैदान में हज कैंप की तैयारियों का संयुक्त निरीक्षण

हज व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व विभाग दिल्ली सरकार (मुख्यालय) के उपायुक्त एवं मध्य जिला के डीएम जी. सुधाकर के नेतृत्व में दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान का संयुक्त निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान दिल्ली नगर निगम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. संयुक्त निरीक्षण के दौरान सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हज यात्रियों की सुविधा से जुड़े सभी आवश्यक कार्य तेजी से पूरे किए जाएं. अधिकारियों को कहा गया कि रामलीला मैदान में हज कैंप से संबंधित सभी व्यवस्थाएं आगामी अप्रैल के पहले सप्ताह तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

18 अप्रैल से शुरू होगी हज यात्रा, 20 मई तक चलेगी प्रक्रिया

हज 2026 की यात्रा 18 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक जारी रहेगी. इस दौरान दिल्ली स्टेट हज कमेटी की व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 22 हजार हज यात्री दिल्ली से पवित्र हज यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आवास व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित विभागों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.

कांग्रेस के नेता और अय्यर

विद्रोही स्वभाव के बावजूद, पूर्व कांग्रेस मंत्री और अब पार्टी के आलोचक बने मणिशंकर अय्यर इस मुद्दे पर अपनी मूल पार्टी कांग्रेस के साथ ही खड़े दिखाई देते हैं, वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने न केवल उन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी दिया। अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में रहे हैं और उन्हें अक्सर उनका दाहिना हाथ कहा जाता था। आज वे राजनीतिक परिदृश्य में कुछ हद तक हाशिये पर हैं लेकिन दिवंगत नेता के प्रति निष्ठा और उनकी पत्नी सोनिया गांधी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहते हैं, भले ही उनके मन में उनके इकलौते पुत्र और कांग्रेस के संभावित उत्तराधिकारी राहुल गांधी को लेकर कई शिकायतें क्यों न हों। पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव के बढ़ने, हालात के बिगड़ने और व्यापक संघर्ष की आशंका के बीच, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस इजराइल यात्रा की कड़ी आलोचना की जो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले से महज दो दिन पहले हुई थी। कांग्रेस ने इस यात्रा को अनुचित समय पर और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि इससे पक्षपातपूर्ण झुकाव और बिना उकसावे के आक्रामक कार्रवाई के मौन समर्थन की छवि बनती है। अय्यर ने दोनों से आगे बढ़कर टिप्पणी की। दोनों दलों के बीच शब्दों का युद्ध शुरू होने से पहले ही अय्यर ने मोदी के इजराइल रवाना होने से ठीक पहले उन्हें निशाने पर लिया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि शायद प्रधानमंत्री अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दें। अय्यर ने कहा था, मैं एक भारतीय प्रधानमंत्री के उस व्यक्ति से मिलने जाने का विरोध करता हूं जिसे मैं नरसंहार का जिम्मेदार और दोषी ठहराया गया युद्ध अपराधी (बेंजामिन नेतन्याहू) मानता हूं। उस समय अय्यर की तरह दुनिया के बाकी लोग भी इस बात से अनजान थे कि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के कुछ ही दिनों के भीतर वह देश ईरान पर बमबारी करेगा। यदि भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार की बात पर विश्वास किया जाए तो सैन्य कार्रवाई का समय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान तय नहीं हुआ था। उन्होंने मीडिया से कहा, यह एक परिचालन अवसर था जो प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल से रवाना होने के बाद ही सामने आया। उन्होंने आगे बताया, हमले को मंजूरी सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल छोड़ने के दो दिन बाद दी। हाल ही में अय्यर तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने राहुल गांधी से दूरी बनाते हुए कहा कि वे राहुलियन नहीं, बल्कि राजीवियन हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बहुत अच्छे से जानने वाले अय्यर ने कहा कि उन्हें उनके मित्र राजीव गांधी के बेटे ने ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उल्लेखनीय है कि अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी से दूरी बनाते हुए दिए गए उनके बयान कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा रहे, जबकि पार्टी ने भी राहुल गांधी से जुड़े उनके बयान से खुद को अलग करने में देर नहीं लगाई। यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, जो अय्यर की टिप्पणियों को प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर आलोचक राहुल गांधी के खिलाफ नया राजनीतिक हथियार मान रही है। राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री पर हमला करने के अवसर तलाशते रहते हैं। अय्यर ने कहा, मैं राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं जानता। हालांकि 13 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वे पंचायती राज के मुद्दे पर मुझसे सहमत हैं और मैं सौ प्रतिशत सही हूं लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया, वह यह था कि अपनी मां से कहकर मुझे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया। मुझसे सहमति जताने के तुरंत बाद ही उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अय्यर ने यह भी कहा कि वे आज तक उस जटिल मानसिकता के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब अय्यर पर चारों ओर से निशाना साधा जा रहा था तब सोनिया गांधी ही उनके साथ खड़ी रहीं। अय्यर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी ने कभी मुझ पर पूरा भरोसा किया लेकिन उन्होंने अपने पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनके मित्रों का ख्याल रखने का दायित्व अपने ऊपर लिया, मानो कंधे पर हाथ रखकर साथ देना। अगर वह न होतीं तो शायद मुझे कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाता और न ही चार मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिलती। यह सब उन्होंने ही किया। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता और वह हाथ जिसने कभी अय्यर की रक्षा की थी, अंततः जानबूझकर हटा लिया गया। अय्यर ने कहा, 2010 में पी. चिदंबरम ने मेरे खिलाफ शिकायत की और सोनिया गांधी ने मुझसे उसी कठोरता से बात की, जैसे कोई स्कूल का प्रधानाचार्य करता है। उसके बाद से वह आशीर्वाद भरा हाथ हट गया। इसलिए मैंने 'स्वर्ग खोने' का अनुभव किया है, हालांकि अब भी उम्मीद करता हूं कि वह स्वर्ग फिर मिल जाएगा। हालांकि यह उम्मीद शायद सिर्फ एक ख्वाहिश ही हो, क्योंकि अय्यर को कई लोग, यहां तक कि सोनिया गांधी भीअनियंत्रित बयान देने वाला मानते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने अपने दिवंगत पति के इस सहयोगी को जगह देने से भी परहेज किया। खुद को समय चुनकर बोलने वाला बताते हुए अय्यर कहते हैं कि अब उन्होंने खुलकर बोलने और सच को सच कहने का फैसला किया है। वे यह स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करते कि शुरुआत में उनकी राय राजीव गांधी के बारे में बहुत अच्छी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर, 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वे राजीव गांधी के खिलाफ वोट देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में शामिल होने के बाद उनकी राय बदल गई। अय्यर ने कहा, मैं यह देखकर हैरान था कि इस व्यक्ति ने एक के बाद एक उन समस्याओं को उठाया जिन्हें उनकी मां इंदिरा गांधी 18 वर्षों में भी हल नहीं कर सकीं। पहले पंजाब, फिर असम और फिर मिजोरम, हर मामले में उन्होंने समाधान का रास्ता निकाला। फिर भी उनमें वही कमजोरी थी जिससे नेहरू-गांधी परिवार ने नेहरू के समय से जूझा है, गलत निर्णय लेना। राहुल गांधी के सलाहकारों की आलोचना करते हुए भी अय्यर कई अन्य लोगों की तरह राहुल की बहन और सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उम्मीद की किरण देखते हैं।

युद्ध और आम नागरिक

एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध को लेकर भयंकर हाहाकार मचा हुआ है और पूरी दुनिया भीषण आर्थिक झंझावतों से जूझने के कगार पर पहुंच गई है तो भारत में संसद का सत्र चालू है जिसमें इस मामले को लेकर विदेश मन्त्री श्री एस. जयशंकर बयान दे चुके हैं कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और वह हर मामले का शान्तिपूर्ण हल चाहता है परन्तु युद्ध की विभीषिका इतनी प्रबल होती है कि चाहे-अनचाहे यह दुनिया के विभिन्न शान्ति प्रिय देशों को भी अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखती है। अतः भारत में पश्चिम एशिया के युद्ध के जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उसे हम सब देख रहे हैं। इस मामले में अभी तक सबसे बड़ा बुरा असर ईंधन गैस की सप्लाई पर पड़ा है और पूरे देश में इसकी किल्लत महसूस की जाने लगी है परन्तु इसके लिए सीधे सत्तारूढ़ सरकार को दोषी बता देना भी कदापि उचित नहीं है क्योंकि भारत 80 प्रतिशत से अधिक ईंधन गैस की आपूर्ति आयात द्वारा ही करता है। पश्चिम एशिया का युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां युद्ध के सभी नियम धराशायी हो रहे हैं और ईरान व इजराइल तथा अमेरिका एक-दूसरे की ताकत को खत्म कर देने की कोशिश में सभी नैतिक मानदंडों को ताक पर रख रहे हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में पैट्रोलियम कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले यह समझना होगा कि यह लड़ाई पूरी तरह गैर संवैधानिक व नियम विरुद्ध है जो अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प की जिद की वजह से शुरू हुई है। श्री ट्रम्प ने युद्ध शुरू करते हुए अपना लक्ष्य बताया था कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस क्रम में उन्होंने ईरान पर हमला करके उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या तक कर दी परन्तु ईरान में वहां की राष्ट्रवादी जनता ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और वह ईरान की सत्ता पर काबिज दूसरी पंक्ति के नेताओं के पीछे चलने लगी। इसके बाद ईरान ने इस युद्ध में अपनी पूरी सामरिक शक्ति व सामर्थ्य को झोंकते हुए पूरे खाड़ी व पश्चिम एशियाई इलाकों के विभिन्न देशों में स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करना शुरू किया और अपने नियन्त्रण में होर्मुज के जलडमरू मध्य के समुद्री मार्ग को एक हथियार बनाना शुरू किया जिससे पूरी दुनिया का 20 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का दुनिया के विभिन्न देशों को यातायात किया जाता है। अब इस जलडमरू मध्य से ईरान केवल कुछ गिने-चुने देशों के जहाजों को छोड़ कर अन्य देशों के जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है और चेतावनी दे रहा है कि यदि ऐसा करने का प्रयास किन्हीं अन्य देशों ने किया तो उसके गंभीरतम परिणाम होंगे। युद्ध में जब ऐसा मुकाम आता है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व रणनीतिक समीकरण बदलने लगते हैं। अतः हम आज जो कुछ भी होर्मुज जलडमरू मध्य में देख रहे हैं वह केवल युद्ध के दुष्परिणाम ही हैं। जहां तक खाड़ी व अरब देशों का सवाल है तो वे भी इस युद्ध में अमेरिका के सहयोगी बने रहने का परिणाम भुगत रहे हैं। मगर इस युद्ध से केवल कच्चे तेल के भाव ही प्रभावित हों ऐसा नहीं है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक पोतों का मुख्य मार्ग है जिसकी वजह से विभिन्न देशों में अन्य सामान की सप्लाई भी प्रभावित होती है यही वजह है कि भारत में केवल ईंधन गैस की किल्लत होने से ही इसके महानगरों के होटलों व रेस्टोरेंटों के व्यापार में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। इतना ही समुद्री व्यापारिक मार्गों के अवरुद्ध होने की वजह से अन्य वस्तुओं पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत इस संकट का मुकाबला किस प्रकार करे? जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो भारत ने रूस से इसका आयात बढ़ा दिया है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए विश्व के दूसरे उत्पादक देशों के साथ अनुबन्ध करने शुरू कर दिये हैं। इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि इस अनचाहे संकट का हम भारतवासी किस प्रकार मुकाबला करें जिससे हमारे कष्ट कम से कम हो सकें। इस सन्दर्भ में हमारी संसद के चल रहे सत्र का महत्व बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि पूरी संसद समवेत स्वर में कह सकती है कि मौजूदा सरकार को केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे आम भारतीयों को कम से कम कष्ट भोगना पड़े। बेशक भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है परन्तु इसका मुख्य ध्येय केवल आम नागरिक का बहुआयामी विकास ही है। यह कार्य तभी हो सकता है जब हम अपनी लोकतान्त्रिक प्रणाली का उपयोग संकटकालीन परिस्थितियों में सर्वदलीय मतैक्य स्थापित करने के लिए करें। इस काम में सरकार को ही सबसे पहले आगे बढ़कर आना होगा और विपक्षी दलों को विश्वास में लेना होगा और साथ ही विपक्षी दलों को भी अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभों को दरकिनार करते हुए आम नागरिक के साथ खड़ा होना होगा लेकिन हमने देखा कि लोकसभा में कल इसके अध्यक्ष के विरुद्ध रखे गये अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया जो ध्वनिमत से ही गिर गया। आज सदन में इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जायजा लेते हुए अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने लगभग 28 मिनट का वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने सदन की प्रतिष्ठा व मान-मर्यादा को नियमानुसार बनाये रखने का संकल्प दोहराया। हमारी संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली पर अंगुली उठाने की गुंजाइश इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हमने जिस संविधान के तहत इस प्रणाली की स्थापना की है उसमें सभी प्रकार के मतों को समाहित करने का सामर्थ्य है बशर्ते वे केवल अहिंसक मार्ग के हों। अतः असली सवाल उस राष्ट्रबोध का है जिसके तहत समूची प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नतमस्तक रहती है।

सम्पादकीय...

सी.बी.आई.- अपने आका की आवाज, सांठगांठ का ब्यूरो

मध्य -पूर्व में ईरान के विरुद्ध अमरीका और इसराईल द्वारा युद्ध छेड़ने के बाद सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो भारत में भाजपा और 'आप' सी.बी.आई. की विशेष अदालत द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को दिल्ली आबकारी नीति 2021 के मामले में अनियमितता और रिश्वतखोरी में भूमिका के लिए उन्हें बरी करने से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। स्पष्ट रूप से सी.बी.आई. इस निर्णय से असहमत है और वह अपील करेगी किंतु अभी तक 2009 के 2जी घोटाले में अंतिम निर्णय नहीं आया और वह अभी उच्च न्यायालय में ही पड़ा है। किंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी समाज षड्यंत्र, अपराध और भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं है। अमरीका ने एपस्टीन फाइल खोली। इस मामले में केजरीवाल की 'आप' कटघरे में थी, जिससे उनकी पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और यही पिछले वर्ष दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्य मुद्दा बना, जिसमें भाजपा की जीत हुई। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे राजनेता हमेशा सी.बी.आई. जांच की मांग क्यों करते हैं। जो नेता सत्ता में होते हैं वे एजेंसी को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। यह एक दंतविहीन शेर है जो अपने मित्रों की सहायता करता है और विरोधियों के साथ राजनीतिक हिसाब चुकता करता है, क्लीन चिट देता है, राजनीतिक लीपापोती करता है और कानून प्रवर्तकों को कानून तोड़ने वाला और अपराध तथा भ्रष्टाचार को वैध बनाता है। ऐसे अनेक आरोप हैं कि एजेंसी का उपयोग किस तरह राजनीतिक विरोधियों को धमकाने और दबाने के लिए किया जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो या मोदी सरकार में। राजनीतिक विरोधियों पर छापे डाले जाते हैं और इसमें प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग एजेंसी के सहयोगी बन जाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, घंटों तक पूछताछ की जाती है, चार्जशीट बनाई जाती है। महत्वपूर्ण मामले में धीमी कार्रवाई की जाती है, जांच में गड़बड़ी की जाती है या उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है या बिल्कुल नहीं की जाती। परिणामस्वरूप होता यह है कि अंततः सी.बी.आई. मामले को सिद्ध नहीं कर पाती। यदि ऐसे मामले में आरोपी मान जाता है तो दबाव कम कर दिया जाता है और यदि नहीं मानता तो दबाव बढ़ा दिया जाता है। दुखद तथ्य यह है कि आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो भी दल सत्ता में आता है, सी.बी.आई. उसकी कठपुतली बन जाती है। अपने विरोधियों को दबाने के लिए सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया जाता है, चाहे कोई भी दल सत्ता में हो। देश के 19 राज्यों में विभिन्न अदालतों में सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 3211 मामले लंबित हैं। इनमें कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनकी जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है। इससे एजेंसी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है क्योंकि वह आरोपों के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती। इससे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर भी आशंकाएं पैदा होती हैं। सी.बी.आई. जांच में मुख्य बात यह होती है कि हमेशा कहा जाता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, किंतु सत्तारूढ़ वर्ग द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध सी.बी.आई. को एक औजार बनाया जाता है।

क्या ट्रंप की शक्ति-प्रदर्शन की आदत दुनिया को तबाही की ओर धकेल रही है?

यह युद्ध—अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध, नैतिक दृष्टि से संदिग्ध और मानवीय दृष्टि से विनाशकारी–किसी भी ठोस और वैध कारण से रहित प्रतीत होता है। यह संघर्ष वास्तविक सुरक्षा चिंताओं से अधिक शक्ति-प्रदर्शन, भू-राजनीतिक पुनर्संरचना और राजनीतिक अहंकार का परिणाम लगता है। इसका प्रभाव केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं है; इसने दुनिया भर के देशों में भय, अस्थिरता और आर्थिक संकट की आशंका को जन्म दिया है। हमले अत्यधिक सैन्य शक्ति के साथ शुरू हुए। अमेरिकी मिसाइलों, ड्रोन और इजराइली लड़ाकू विमानों ने तेहरान, इस्फहान, कोम और अन्य शहरों में सैन्य तथा रणनीतिक लक्ष्यों पर प्रहार किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या की खबर भी सामने आई, साथ ही परमाणु प्रतिष्ठानों, मिसाइल ठिकानों और सैन्य कमान केंद्रों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी प्रशासन का घोषित लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना, उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और अंततः शासन परिवर्तन को मजबूर करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है, जिससे स्पष्ट है कि यह केवल सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक दबाव की रणनीति है। लेकिन इस युद्ध के लिए प्रस्तुत किए गए औचित्य लगातार बदलते रहे हैं–कभी आसन्न खतरे की बात, कभी परमाणु कार्यक्रम को रोकने की आवश्यकता, और कभी बैलिस्टिक मिसाइलों को समाप्त करने का तर्क। स्वतंत्र विश्लेषकों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार किसी भी तत्काल या प्रत्यक्ष खतरे का स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। यह स्थिति 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाती है, जब संदिग्ध और बाद में झूठे साबित हुए दावों के आधार पर युद्ध छेड़ा गया था, जिसने पूरे क्षेत्र को दशकों तक अस्थिर कर दिया। इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। पहले ही सप्ताह में ईरान में नागरिकों की मौतें हजार से

अधिक बताई जा रही हैं। दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबरों ने दुनिया को झकझोर दिया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार युद्ध और उससे उत्पन्न आंतरिक अशांति में मरने वालों की संख्या हजारों से लेकर दसियों हजार तक पहुंच सकती है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, अस्पतालों और नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है, और क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस तनाव का एक बड़ा परिणाम होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना है–दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक। इसके कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा, खाद्य और वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है। सबसे अधिक नुकसान गरीब और आयात-निर्भर देशों को झेलना पड़ रहा है। युद्ध का एक प्रमुख तर्क ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम को बताया जा रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कई बार कहा है कि वह यह साबित नहीं कर सकी कि ईरान सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बना रहा था। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने भी बार-बार कहा था कि परमाणु हथियार इस्लाम में हराम हैं और उन्होंने उनके खिलाफ एक धार्मिक फतवा जारी किया था। ईरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। फिर भी कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि परमाणु हथियारों का अभाव ही ईरान की कमजोरी बन गया। उनका कहना है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं–जैसे उत्तर कोरिया या पाकिस्तान–उन पर सीधे सैन्य हमले का जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु प्रतिरोध संभावित आक्रमण को रोकता है। इस युद्ध की वैधता भी गंभीर प्रश्नों के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई केवल दो परिस्थितियों में वैध होती है–आत्मरक्षा में, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से। इस मामले में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती दिखती। यूरोपीय नेताओं, अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों और कई देशों ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। अमेरिका के भीतर भी संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है, जबकि 1973 का War Powers Resolution राष्ट्रपति को सीमित समय के भीतर कांग्रेस की अनुमति लेने के लिए बाध्य करता है। आलोचकों का कहना है कि इन प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई है। इस युद्ध के खिलाफ अमेरिका के भीतर भी महत्वपूर्ण विरोध उभर रहा है। कई सर्वेक्षणों के अनुसार अमेरिकी जनता का बड़ा हिस्सा सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। वॉशिंगटन डी.सी., न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुछ नागरिक संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संभावित युद्ध अपराधों की जांच की मांग भी की है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के राजनीतिक आधार के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद सामने आ रहे हैं, जहां कुछ लोग इसे अमेरिका फर्स्ट नीति से विचलन मानते हैं। दुनिया के कई देशों ने इस युद्ध पर चिंता जताई है। यूरोप के कई सहयोगी इसमें शामिल होने से पीछे हट गए हैं। रूस ईरान को खुफिया जानकारी देने की बात कर रहा है, जबकि चीन स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा है। भारत सहित कई ऊर्जा-आयातक देशों के लिए यह संघर्ष आर्थिक और रणनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है; यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में तत्काल बहस और जांच शुरू करनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस को भी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए युद्ध की समीक्षा करनी चाहिए। भारत जैसे देशों के लिए, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं और क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं, कूटनीतिक दबाव बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि दुनिया चुप रहती है, तो यह मिसाल भविष्य में और भी खतरनाक सैन्य हस्तक्षेपों को वैधता दे सकती है। आखिरकार, सच्ची सुरक्षा शक्ति-प्रदर्शन से नहीं बल्कि न्याय, संयम और संवाद से आती है। बम और मिसाइलें केवल विनाश लाती हैं–और उनके सबसे बड़े शिकार हमेशा आम नागरिक ही होते हैं। दुनिया को अब स्पष्ट संदेश देना होगा बिना किसी वैध कारण के युद्ध

युद्ध के बावजूद ईरान की हवा साफ, मगर शांति के बावजूद दिल्ली, मुंबई में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर

देखा जाये तो वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के फेफड़ों के विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। एक हालिया वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लगभग सत्रह लाख अठारह हजार लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। युद्ध क्षेत्र में उठने वाला धुआं भले ही डरावना दिखाई दे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार भारत के शहरों में फैला स्थायी प्रदूषण कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और एक तरह से अदृश्य हत्यारा बन जाता है। बहरहाल, इस पूरी स्थिति से एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों के उत्सर्जन, उद्योगों के धुएं, निर्माण धूल और पराली जलाने जैसी समस्याओं पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।

पश्चिम एशिया इस समय युद्ध की आग में झुलस रहा है। लेबनान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल हमले और बमबारी जारी है। कई शहरों के ऊपर तेल और धुएं के काले गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इन युद्ध प्रभावित इलाकों की हवा भारत के कई प्रमुख शहरों से कहीं ज्यादा साफ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के आंकड़े बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में भी हवा का स्तर दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय महानगरों से बेहतर बना हुआ है। 11 मार्च 2026 को भारतीय समयानुसार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता मंच एक्यूआई डाट इन के आंकड़ों के अनुसार तेहरान का एक्यूआई लगभग 33 दर्ज किया गया, जबकि उसी समय दिल्ली का एक्यूआई 63 था। दिन के दौरान भी स्थिति इसी तरह रही। दोपहर बारह बजे तेहरान का अधिकतम एक्यूआई 47 रहा, जो अच्छे स्तर में आता है। इसके विपरीत दिल्ली में सुबह आठ बजे एक्यूआई 323 तक पहुंच गया, जो अत्यंत खराब श्रेणी में आता है। यह स्थिति तब है जब तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में तेल भंडार और ऊर्जा ढांचे पर हमलों के कारण धुएं और जहरीली गैसों की आशंका बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आठ मार्च की रात तेहरान के ऊपर काले धुएं के घने बादल दिखने के दृश्य सामने आए थे। यहां तक कि कुछ इलाकों में काली वर्षा की भी खबरें आईं, जो तेल भंडार में लगी आग और रासायनिक धुएं का परिणाम मानी जा रही है। लोगों ने गले में जलन और आंखों में खुजली की शिकायत की, और प्रशासन ने नागरिकों को घर के भीतर रहने की सलाह दी। इसके बावजूद वास्तविक समय के आंकड़े बताते हैं कि तेहरान में एक्यूआई अधिकतर समय शून्य से पचास के बीच यानी स्वस्थ श्रेणी में बना रहा। यह तथ्य भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है क्योंकि भारत के कई महानगरों में वायु प्रदूषण लगातार खराब, बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में प्रदूषण की समस्या मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से पैदा होती है। सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। तेजी से बढ़ती निजी गाड़ियों की संख्या नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणों को बढ़ाती है। यही वजह है कि दिल्ली के साथ-साथ बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहर भी समय समय पर खराब हवा से जूझते रहते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य से उठने वाली धूल, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले धुएं तथा ईंट भट्ठों से उत्सर्जित गैसें भी प्रदूषण को बढ़ाती हैं। डीजल जनरेटर से निकलने वाला धुआं और सड़कों की धूल इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं। ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर और जैव ईंधन जलाने से भी हवा में प्रदूषण बढ़ता है। उत्तर भारत में एक और महत्वपूर्ण कारण खेतों में पराली जलाना है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से धुआं बड़ी मात्रा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंचता है और सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब कर देता है। भौगोलिक स्थिति भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक तरह के निचले बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। इस कारण प्रदूषक तत्व यहां फंस जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। साथ ही उत्तर पश्चिम से बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की ओर से आने वाली धूल भी प्रदूषण को बढ़ाती है। इसके विपरीत तेहरान, तेल अवीव, बेरूत और दुबई जैसे कई पश्चिम एशियाई शहर समुद्र के नजदीक स्थित हैं या ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां हवाएं प्रदूषकों को तेजी से फैलाकर साफ कर देती हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण हवा का प्रवाह बेहतर रहता है और प्रदूषण का जमाव कम होता है। वहीं मुंबई समुद्र किनारे होने के बावजूद प्रदूषण से जूझता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण स्थानीय स्रोत हैं, खासकर वाहनों की अत्यधिक संख्या। मुंबई में वाहनों का घनत्व कई शहरों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, इसलिए यहां प्रदूषण का स्तर भी ऊंचा बना रहता है। इसके अलावा, युद्ध से होने वाला प्रदूषण भी एक अलग प्रकृति का होता है। बमबारी या आग लगने से भारी मात्रा में धुआं और जहरीली गैसें निकलती हैं, लेकिन यह प्रदूषण अक्सर अस्थायी होता है। जब आग बुझ जाती है या घटना समाप्त हो जाती है तो उस स्रोत से निकलने वाला प्रदूषण भी रुक जाता है। इसके विपरीत वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्य से निकलने वाला धुआं लगातार हवा में जाता रहता है, जिससे लंबे समय तक प्रदूषण बना रहता है। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल के दिनों में दिखाई दी गई स्मॉग को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह ईरान में तेल रिफाइनरी पर हमलों से जुड़ी हो सकती है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह स्मॉग दरअसल पश्चिमी हवाओं के साथ आई मरुस्थलीय धूल का परिणाम है। हम आपको बता दें कि पांच से सात मार्च के बीच बलूचिस्तान और मध्य पाकिस्तान से चली तेज पश्चिमी हवाएं राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर गुजरीं और बड़ी मात्रा में धूल को उत्तर पश्चिम भारत तक ले आईं। हवा में तैरते ये धूल कण आकाश को धूसर और भूरा बना देते हैं और दृश्यता कम कर देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में हुए विस्फोटों का प्रदूषण भारत तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच लगभग ढाई से तीन हजार किलोमीटर की दूरी है। इतनी लंबी दूरी तय करते समय प्रदूषक तत्व काफी कमजोर हो जाते हैं। देखा जाये तो वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के फेफड़ों के विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। एक हालिया वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लगभग सत्रह लाख अठारह हजार लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। युद्ध क्षेत्र में उठने वाला धुआं भले ही डरावना दिखाई दे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार भारत के शहरों में फैला स्थायी प्रदूषण कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और एक तरह से अदृश्य हत्यारा बन जाता है। बहरहाल, इस पूरी स्थिति से एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों के उत्सर्जन, उद्योगों के धुएं, निर्माण धूल और पराली जलाने जैसी समस्याओं पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। जब तक इन स्रोतों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक देश के शहरों में स्वच्छ हवा का सपना अधूरा ही रहेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साय पैंफलचला एस. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/0882)

गैस की कालाबाजारी रोकने को ठोस कदम उठाये प्रशासन

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बर्तन बाजार में प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता के कार्यालय पर आहूत की गईं जिसमें अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जॉनी ने कहा कि वैश्विक युद्ध की स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सीएनजी ,पीएनजी ,पेट्रोल, डीजल ,केरोसिन किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है मुरादाबाद के सभी व्यापारी भाइयों से हम अपील करते हैं कि कोई भी व्यापारी जो इन वस्तुओं को विक्रय करता है अनावश्यक रूप से किसी भी उपभोक्ता को परेशान ना करें कोई भी कालाबाजारी ना करें। प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वह परेशान न हो 25 दिन में औसत एक सिलेंडर चलता है अगर कोई भी 'यादा रकम मांगता है तो संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से संपर्क करे उत्तर प्रदेश सरकार और मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह की पूरी टीम सब पर नजर है किसी भी चीज की कमी नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से सुनील अग्रवाल ,सुधीर कंसल,मोहित अग्रवाल, हरिओम गुप्ता ,मनीष बेरी ,मोहित खन्ना अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद रहे।

सखी पहल के तहत 237 छात्राओं को 5 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति

बहराइच ।

जनपद में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल रक्षा भारत एवं केन्वयू के सहयोग से संचालित सखी पहल द् टू सिक्योर हर फ्यूचर÷ परियोजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वा नन्द के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस पहल के तहत जनपद बहराइच के 16 हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों की 237 छात्राओं को 5000 रुपये की सखी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच समेत पांच जिलों में कुल 1200 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वा नन्द ने सखी छात्रवृत्ति पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

इससे पढ़ाई से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में मदद मिलती है और छात्राओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि यह पहल छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सखी पहल परियोजना के अंतर्गत किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, जीवन कौशल और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों पर नियमित जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही स्कूलों में वॉश सुविधाओं को सुदृढ़ करने, पैड बैंकों की स्थापना, तथा मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के नवीनीकरण जैसी पहलें भी की जा रही हैं, ताकि छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पढ़ाई जारी रखने में सुविधा मिल सके। परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों के लिए लैंगिक-संवेदनशील शिक्षण पद्धति पर प्रशिक्षण, छात्राओं के लिए जीवन कौशल और आत्मरक्षा से जुड़े सत्र,

स्कूलों में पैड बैंक और वॉश सुविधाओं को भी बढ़ावा

तथा समुदाय स्तर पर बाल विवाह रोकथाम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हुए उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्राएँ तथा बाल रक्षा भारत की टीम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अखिलेश शुक्ल प्रोजेक्ट अस्सिस्टेंट जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे छात्राओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

सेवा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करना है उद्देश्य- सुनीता

बहराइच।

राष्ट्र सेविका समिति बहराइच विभाग द्वारा नगर के सी के लॉन स्थित प्रांगण में होली मिलन के कार्यक्रम का हुआ आयोजन कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर तेजस्विनी चोगले ने की मंच पर माननीय जिला संचालिका छवि राय तानी एवं मुख्य वक्ता विभाग कार्यवाही का सुनीता रही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य है समाज में संस्कार सेवा संगठन और राष्ट्र भावना को मजबूत करना होली मिलन का यह कार्यक्रम हमें आपस में प्रेम सहयोग और आत्मीयता के रंगों से जोड़ने का अवसर देता है इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लेकर अपने जीवन में सेवा संस्कार और राष्ट्रभक्ति के भाव को और अधिक मजबूत करेंगे तथा समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे । कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही डॉक्टर तेजस्विनी ने कहा कि वैदिक काल से ही महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिलाएं कभी भी अबला नहीं रही है हम सभी महिला दिवस मनाते हैं परंतु भारतीय संस्कृत में हर दिन महिलाएं सभी पर तो ध्यान दे देती है परंतु अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाती है उन्हें अपने

महिलाएं कभी भी अबला नहीं रही है - चोगले धूमधाम से आयोजित हुआ होली मिलन कार्यक्रम

ऊपर भी ध्यान देना चाहिए चाहिए उन्होंने मेडिटेशन के विषय में जागरूक किया माननीय संचालिका छवि जी ने बताया कि होली रंगों का उत्सव है होली पर हम सभी एक दूसरे के गिले शिकवे भुला कर गले मिलते हैं मंच संचालन जिला कार्यवाहीका शीला जी ने किया इस अवसर पर नानपारा की जिला कार्यवाहीका प्रियंका यादव, विचार परिवार से एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, श्रुति महेश्वरी, माधुरी सिंह,स्वाति तिवारी, शिखा त्रिपाठी, हेमा निगम, प्रियंका रावत,जिला बौद्धिक प्रमुख डॉ मनीष खन्ना ,तरूणी प्रमुख सुरभि, जिला शारीरिक प्रेरणा, सेवा प्रमुख नीलम, नगर कार्यवाहिका रीना ,सह नगर कार्यवाहीका साधना, श्वेता, रेखा, गरिमा, नगर शारीरिक प्रमुख तमन्ना, नगर संपर्क प्रमुख शांति पांडे सहित समिति की अन्य दायित्वधारी बहने एवं समाज प्रतिष्ठित हस्तियां भी उपस्थित रहीं।

ओडिशा भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश का आलू: दिनेश प्रताप

आलू किसानों के हित में मुरादाबाद में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन संपन्न

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार, मुरादाबाद में एक महत्वपूर्ण क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सत्र में आलू की उपज के समुचित भंडारण, बेहतर बाजार मूल्य और सुलभ विपणन सुनिश्चित कर किसानों के हितों की रक्षा करना रहा। इस सम्मेलन में मुरादाबाद, बरेली, मेरठ एवं सहारनपुर मंडलों के अंतर्गत आने वाले 17 जनपदों (मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, शामली एवं मुजफ्फरनगर) के प्रमुख शीतगृह स्वामियों, आलू उत्पादकों, व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।
रा'यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु ओडिशा सरकार से वार्ता की चुकी है। अब उत्तर प्रदेश का आलू ओडिशा के बाजारों में भेजा जाएगा।

प्रदेश स्तर पर जल्द ही कृषि निर्यात बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें संभल के एफपीओ निदेशक दीपक शर्मा को भी शामिल किया जाएगा।
प्रगतिशील किसान कुलवीर सिंह चहल ने रसायनों के अत्यधिक उपयोग से गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री जी ने रसायनों का उपयोग कम करने और गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया।
सम्मेलन के दौरान जिला उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल ने बताया कि जनपद संभल द्वारा आलू की 15 विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। उत्कृष्ट कार्य हेतु मंत्री द्वारा संभल के विकास अग्रवाल एवं दीपक शर्मा को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
कृषि विपणन निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मंत्री जी को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में बाजार में अधिक आवक के कारण किसानों को कम मूल्य प्राप्त हो रहा है, जिसे सुधारने हेतु निर्यात और अंतररा'ट्रीय व्यापार के प्रयास तेज किए गए हैं। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त एवं डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, विधायक रितेश कुमार गुप्ता एवं विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, जिला अध्यक्ष, आकाश पाल सहित उद्यान, कृषि विपणन और मण्डी समिति के अधिकारी उपस्थित रहे।

आयोग की सदस्या ने की महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई

मुरादाबाद।

सदस्य राज्य महिला आयोग संगीता जैन द्वारा सर्किट हाउस मुरादाबाद में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जनसुनवाई की गई। महिला जनसुनवाई में सदस्य के समक्ष तीन शिकायतें आई जिनका तत्काल निराकरण कर दिया गया। सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश रा'य महिला आयोग प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय जलाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। कोई भी महिला परेशान न हो यदि किसी महिला को समस्या है तो उसकी तत्काल

सुनवाई कर न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बने अपनी समस्याओं को छुपाए नहीं बल्कि निर्भीक होकर अपनी समस्या को बताएं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग महिलाओं की शिकायतों /समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर उपनिदेशक महिला कल्याण श्री राजेश चंद्रगुप्त, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विकास सिंह, सीओ सिविल लाइन कुलदीप कुमार गुप्ता, एसएचओ महिला थाना वंदना सिंह, राजकीय महिला शरणालय से प्रेरणा सिंह जेल अधीक्षक आलोक सिंह, सहित समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, श्रम विभाग आईसीडीएस, महिला कल्याण एवं अन्य विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

गहोई वैश्य सभा ने यूपीएससी में चयनित गरिमा सिंह को किया सम्मानित

मुरादाबाद।

गहोई वैश्य सभा ने मुरादाबाद की मानसरोवर निवासी गरिमा सिंह को यूपीएससी में उनकी 240 रैंक आने पर उनके आवास पर पहुंचकर गणेश जी के चित्र के साथ गीता भेंट की। उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि सफलता का कोई भी शॉर्ट कट नहीं है। उन्होंने कहा कि आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए युवाओं को संपूर्ण मनोयोग से विषय की तैयारी के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्पूर्ण विश्व से जुड़े सामान्य ज्ञान से जुड़े विषयों पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया से जुड़े इंटरनेट का प्रयोग केवल ज्ञान वर्धन के लिए आवश्यक है। बाकी प्लेटफार्म से ध्यान भटकाने का खतरा रहता है। गरिमा ने बताया कि उन्हें आईपीएस अथवा आईआरएस मिलने की पूरी संभावना है। ये दोनों ही सर्विस समाज सेवा के लिए भी एक प्रेरणा है। सम्मान करने वालों में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ विशेष गुप्ता,सभा अध्यक्ष सतीश गुप्ता,पार्षद राजेश गुप्ता,महामंत्री हरिओम गुप्ता तथा हरि मंगल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ राजेश रंजन रहे।

गोबर और मंदिरों के चढ़े फूलों से संवर रही महिलाओं की तकदीर ,गो-उत्पादों से कर रहीं शानदार कमाई

मुरादाबाद। गाय का गोबर अब केवल अपशिष्ट नहीं रहा, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का एक मजबूत आधार बन गया है। कान्हा गौशाला में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं गोबर और मंदिरों से निकलने वाले अपशिष्ट फूलों का इस्तेमाल कर बेहतरीन उत्पाद तैयार कर रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि ये महिलाएं रोजाना करीब 500 रुपये तक की कमाई कर आत्मनिर्भर भी बन रही है। कान्हा गौशाला में काम करने वाले प्रशिक्षक अमरीश शर्मा और समूह की सदस्या राधा ने बताया कि गोबर से कई प्रकार की उपयोगी और सजावटी सामग्री तैयार की जा रही है। इनमें मुख्य रूप से गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी की छोटी-बड़ी मूर्तियां, धूपबत्ती, अगरबत्ती, गोबर के गोल व चौकोर उपले, और लक्ष्मी जी के चरण शामिल हैं। इसके अलावा महिलाएं गोबर से ओम और स्वास्तिक के चिह्न भी बना रही हैं, जिन्हें मोबाइल के पीछे लगाने से रेडिएशन कम होने का दावा किया गया है। खास बात यह है कि मंदिरों में चढ़ने वाले अपशिष्ट फूलों को फेंकने के बजाय उन्हें सुखाकर और पीसकर गोबर में मिलाकर विशेष धूपबत्ती तैयार की जा रही है। गोबर से एक दीप यज्ञ कृपा किट भी बनाई जा रही है, जिसमें हवन कुंड, गोबर के दीये, समिधा और हवन सामग्री शामिल होती है। होली के अवसर पर महिलाओं ने गोबर से विशेष बरगुलियों (मालाओं) का निर्माण किया, जो 20 रुपये प्रति माला के हिसाब से बाजार में खूब बिकीं, जिसमें सिर्फ 4 से 5 किलो गोबर की लागत आती है। केंचुए की मदद से वर्मी कंपोस्ट (जैविक खाद) भी बनाया जा रहा है, जो मरते हुए पौधों को भी जीवित कर सकता है। इसके साथ ही महिलाएं सॉफ्ट टॉय (टेडी, डॉगी), लटकन, बंधनवार और लकड़ी के उत्पाद भी बना रही हैं। इस पूरी मुहिम से कैलाश और रहमत (जिसकी सचिव राधा और जबल निशा हैं) जैसे स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। ऐसे 10-10 महिलाओं वाले 5 समूहों को मिलाकर राधा महिला प्रेरणा ग्राम संगठन बनाया गया है और सीएलएफ के तहत कुल 120 समूह काम कर रहे हैं। प्रशिक्षक अमरीश ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने एक अनूठा अभियान प्लास्टिक लाओ, पूजा सामग्री ले जाओ भी शुरू किया है। इसके तहत लोगों को प्लास्टिक कचरा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित किया जाता है और खाली बोतलों में प्लास्टिक भरकर इको-ब्रिक्स तैयार की जा रही हैं।

कोचिंग टीचर का महापाप- तीन छात्राओं का दो साल तक यौन शोषण, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल; छात्रा ने खोली पोल

नई दिल्ली । उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कोचिंग सेंटर के ट्यूटर पर पिछले दो साल से 12वीं कक्षा की तीन छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे है। दरअसल आरोपी शिक्षक धीरज चौधरी ने तीनों छात्राओं को लड़कों के साथ घूमते हुए देख लिया था। आरोपी ने इसका फायदा उठाया। पहले छात्राओं को पीटा। बाद में आरोपी ने छात्राओं ने घर बता देने का डर दिखाकर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। छात्राओं ने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया तो आरोपी उनके घर पहुंच गया और उनके खराब चरित्र की बात परिजनों से करने लगा। एक छात्रा ने हिम्मत दिखाकर परिजनों को सारी बात बताई तो आरोपी पीड़ित के घर की बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गया।

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश - बाद में छात्राएं परिजनों के साथ सोमवार को बुराड़ी थाने पहुंचीं। वहां पर तीनों छात्राओं की काउंसलिंग कराने के बाद उनके बयान लेकर यौन उत्पीड़न, पॉक्सो बंधक बनाने, मारपीट करने व ब्लैकमेल करने की धमकी देने का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों छात्राओं की उम्र 16 और 17 साल के बीच है। तीनों अपने-अपने परिवारों के साथ बुराड़ी इलाके में रहती है। तीनों एक पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस को दिए बयान में एक छात्रा ने बताया कि वह 3 साल से धीरज चौधरी नामक टीचर की कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बाकी दोनों छात्राएं भी यहीं पर आती थीं। पीड़िता ने बताया कि सर किसी न किसी बहाने से हम लोगों को छूते रहते थे। पीड़िता ने विरोध किया तो धमकाकर चुप करा दिया। अक्टूबर 2024 में आरोपी धीरज ने तीनों छात्राओं की कोचिंग सेंटर में पिटाई भी की थी। दरअसल आरोपी ने तीनों को लड़कों के साथ एरिया में घूमते हुए देख लिया था। इसके बाद आरोपी ने दो छात्राओं के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। बाद में दो दिन बाद तीसरी छात्रा को भी आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया। छात्राओं ने परिजनों को बताने की धमकी दी तो आरोपी ने बताया कि उसके पास उनकी अश्लील वीडियो है। वह इसको सोशल मीडिया पर डाल देगा। इसके अलावा वह परिजनों की हत्या भी कर देगा। इस बात पर तीनों छात्राएं बुरी तरह डर गईं। अगस्त के बाद तीनों छात्राओं ने कोचिंग सेंटर ही जाना बंद कर दिया। इस बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था। सोमवार को आरोपी धीरज एक छात्रा के घर पहुंचा और परिजनों से उसकी बुराई करने लगा। यह सुनकर छात्रा ने परिजनों को उसकी हरकत बताई। सोमवार को बुराड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया गया। बुराड़ी इलाके में एक शख्स अपनी छह साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। मासूम इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने ही अस्पताल से पुलिस को खबर दी। बाद में पुलिस ने मासूम से बातचीत के बाद पिता पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। पुलिस के मुताबिक मासूम परिवार के साथ बुराड़ी इलाके में रहती है।

ईरान दो भारतीय गैस टैंकरों को होर्मुज से गुजरने देगा

तेल अवीव/तेहरान । ईरान ने दो भारतीय गैस टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दो भारतीय एलपीजी टैंकर जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की ओर रवाना होंगे। इससे घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक कच्चे तेल का टैंकर भी 1 मार्च के आसपास होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और सऊदी अरब का तेल लेकर चाबिहार तक भारत आ सकता है। इससे पहले गुरुवार शाम को ही भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा था कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में भारत को सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने कहा- भारत और ईरान के बीच लंबे समय से दोस्ताना रिश्ते और आपसी भरोसा रहा है।

ईरान सरेंडर करने वाला है- जी7 देशों की बैठक में बोले राष्ट्रपति ट्रंप, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा

वर्ल्ड डेस्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जी7 देशों के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में यह दावा किया है कि ईरान लगभग आत्मसमर्पण करने वाला है। यह जानकारी एक्सियोस द्वारा शुक्रवार को जी7 देशों के तीन अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित की गई है, जिन्हें इस बातचीत के बारे में जानकारी दी गई थी।

हम सभी को धमकाने वाला कैंसर खत्म- ट्रंप

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसे कैंसर को खत्म कर दिया है जो हम सभी को धमकी दे रहा था। उन्होंने बुधवार की सुबह जी-7 कॉल के दौरान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के परिणामों का भी बखान किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोई नहीं जानता कि नेता कौन है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है जो आत्मसमर्पण की घोषणा कर सके।

ईरान के नेताओं पर ट्रंप की तीखी टिप्पणी

शुक्रवार को, ट्रंप ने ईरान के नेताओं पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध के दो सप्ताह पूरे होने के साथ ही इस क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों के भारी आदान-प्रदान के बीच उन्हें मारना उनका बड़ा सम्मान था।

पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और भारत पर संभावित प्रभाव

यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस क्षेत्र में जारी संघर्ष का भारत पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर। हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी और कूटनीतिक माध्यमों से स्थिति को सुलझाने पर जोर दिया था।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

अफवाहों से बचने की अपील, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही है, वे पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और लगातार रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तेल कंपनियां शेष आपूर्ति को भी पूरी तरह सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक घबराहट या ईंधन तथा गैस का अतिरिक्त भंडारण करने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गैस की किल्लत- एलपीजी की कमी से दिल्ली के स्ट्रीट फूड पर संकट

नई दिल्ली । एलपीजी गैस की कमी के कारण अब दिल्ली वालों की जेब पर भी असर पड़ने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण दिल्ली के 30 से 40 फीसदी होटल, रेस्टोरेंट, छोटे ढाबे और रेहड़ी-पटरी के खाने-पीने के स्टॉल बंद हो गए है, जबकि कई कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच गए है। लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, बुराड़ी, कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट और पहाड़गंज समेत कई इलाकों में कई छोटे होटल और रेस्टोरेंट ने अपना काम बंद कर दिया है। वहीं कुछ होटल सीमित मेन्यू के साथ काम चला रहे है। एलपीजी संकट का सबसे ज्यादा असर रेहड़ी-पटरी के फूड स्टॉल और छोटे ढाबों पर पड़ा है। सुबह से देर रात तक चलने वाले राजधानी के स्टॉलों पर हजारों लोग सस्ता और स्वादिष्ट भोजन करते है। लेकिन गैस की कमी और महंगे सिलिंडरों ने इनकी कमर तोड़ दी है। अधिकांश रेहड़ी-पटरी वाले रोजाना नकद में कमर्शियल सिलिंडर खरीदते है। पहले उन्हें आसानी से सिलिंडर मिल जाता था, लेकिन अब आपूर्ति कम होने के कारण कई गैस सप्लायर बड़े होटल और रेस्टोरेंट को प्राथमिकता दे रहे है। इस कारण छोटे दुकानदारों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है।

पेट पालने के लिए उठा रहे जोखिम

सफदरजंग स्थित रेहड़ी वालों ने बताया कि उन्हें कई-कई दिन तक सिलिंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ दुकानदार मजबूरी में छोटे 5 किलो के अवैध सिलिंडरों का इस्तेमाल करने लगे है। हालांकि यह सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना जाता है, लेकिन पेट पालने के लिए वे यह जोखिम उठाने को मजबूर है। गैस की कीमत बढ़ने से उनकी कमाई पर भी सीधा असर पड़ा है। कई रेहड़ी-पटरी वालों का कहना है कि पहले जहां रोजाना कुछ बचत हो जाती थी, अब गैस महंगी होने के कारण रोजाना की बचत में 200 से 400 रुपये तक की कमी आ गई है। वहीं, होटल और ढाबा संचालकों के अनुसार, गैस सिलिंडर की सप्लाई समय पर नहीं मिल रही है। दूसरी ओर कीमतें इतनी बढ़ गई है कि छोटे कारोबारियों के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है।

कई ढाबे बंद होने की कगार पर

कटवारिया सराय स्थित एक छोटा सा ढाबा कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन एलपीजी की कमी के कारण वह भी अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। यह ढाबा आसपास के ऑफिस कर्मचारियों, टैक्सी चालकों और छोटे कारोबारियों के लिए सस्ता और भरपेट भोजन का प्रमुख ठिकाना माना जाता है। ढाबा मालिक मलखान ने बताया कि उनके यहां रोजाना दो कमर्शियल गैस सिलिंडर की खपत होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिलिंडर की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनके पास सिर्फ एक सिलिंडर बचा हुआ है। अगर जल्द ही नया सिलिंडर नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन ढाबा बंद करना पड़ेगा। ढाबा मालिक के अनुसार, यह ढाबा कई वर्षों से चल रहा है और इसी से उनके परिवार का खर्च चलता है। गैस की कमी के कारण कारोबार बंद होने का डर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है।

खाने-पीने के दामों में बढ़ोतरी

गैस की बढ़ती कीमतों का असर अब खाने-पीने की हर चीज पर दिखाई देने लगा है। कई होटल और ढाबों में चाय, रोटी, सब्जी और स्नैक्स समेत खाने के दाम बढ़ा दिए गए है। कई जगहों पर खाने के दाम 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गए है। ढालका मोड़ इलाके में एक रेस्तरां ने रोटी के दाम में अचानक दो रुपये की बढ़ोतरी कर दी। रेस्तरां मालिक का कहना है कि गैस का दाम बढ़ने के चलते रोटी का दाम भी बढ़ाना पड़ रहा है। खाने-पीने के दामों में बढ़ोतरी का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इससे रोजाना बाहर खाना खाने वाले लोगों का खर्च भी बढ़ गया है। होटल संचालकों के अनुसार, गैस की कीमत बढ़ने के कारण उन्हें मजबूरी में कीमत बढ़ानी पड़ रही है। गैस संकट का असर सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम ग्राहकों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ढाबे में खाना खाने आए बुलंदशहर निवासी रोहित ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी करते हैं और दिल्ली में एक पीजी लेकर रहते है। उन्होंने बताया कि अकेले रहने के कारण वह खुद खाना नहीं बनाते हैं और बाहर से खाते है।

भाजपा की डबल इंजन सरकार, असम के तेज विकास के लिए काम कर रही है- पीएम मोदी

गुवाहाटी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के दो दिवसीय दौरे के दौरान खराब मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव करना पड़ा। प्रधानमंत्री का आज कोकराझार जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद पीएम गुवाहाटी पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

गुवाहाटी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी गुवाहाटी से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमाप्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं यहां से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा-एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। असम माला अभियान के तीसरे चरण से असम की बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी। इससे पहले, पीएम मोदी ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक प्रमुख सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना असम माला 3.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत, अंतर-राज्यीय संपर्क को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों व ग्रामीण सड़कों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए असम भर में 900 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में लगभग 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित छह सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें चार फ्लाईओवर और दो पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं से कोकराझार जिले में यातायात जाम कम करने और संपर्क, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण आवागमन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पीएम मोदी ने कोकराझार जिले के बासबारी में आवधिक मरम्मत (पीओएच) कार्यशाला की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है, जो उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, असम और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी। वहीं नागी-अगरतला एक्सप्रेस असम और त्रिपुरा के बीच संपर्क को सुधारते हुए यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए अंतर-राज्यीय यात्रा को सुगम बनाएगी।

5 नए विकास बोर्ड बनाने का ऐलान

आगामी चुनाव से पहले सीएम बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक

कोलकाता ।

उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंडा, कोरा, डोम, कुंभकार और सदगोप समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी।

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंडा, कोरा, डोम, कुंभकार और सदगोप समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी। सीएम ममता के अनुसार यह कदम न केवल इन कमजोर और पिछड़े समुदायों के अधिकारों और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में तरक्की को भी बढ़ावा देगा। सीएम बनर्जी ने इसे राज्य में समान और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताया है, जो चुनावी मोर्चे पर भी उनकी पकड़ मजबूत कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में सीएम ममता ने लिखा कि मैं खुशी के साथ घोषणा करती हूं कि हमारी सरकार मुंडा (एसटी), कोरा (एसटी), डोम (एससी), कुंभकार (ओबीसी) और सदगोप (ओबीसी) समुदायों के लिए जल्द ही पांच नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी।

ये समुदाय राज्य की सजीव-रंगीन संस्कृति का हिस्सा- सीएम

अपने पोस्ट में सीएम ममता बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये पांचों समुदाय राज्य की सजीव और रंगीन संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। बोर्डों के जरिए इनके भाषा, परंपरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सीएम बनर्जी ने यह भी बताया कि 2013 से उनकी सरकार ने कई ऐसे बोर्ड स्थापित किए हैं, जिससे कमजोर समुदायों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया गया है।

हमारा लक्ष्य समान विकास- सीएम

इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी समुदाय पीछे न रह जाए। उन्होंने जोर दिया कि बंगाल सरकार का लक्ष्य है कि समान विकास और सहयोग के जरिए हर चेहरे पर मुस्कान आए। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने यह घोषणा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सदस्य हैं और चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे में जहां एक ओर सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस चुनाव को अपने पक्ष की बेजोड़ तैयारी में लगी हुई है।

एलपीजी संकट- सरकार मानने को तैयार नहीं कि लोगों को दिक्कत है : डिंपल यादव

लखनऊ। एलपीजी संकट को लेकर समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ब्लंडर जनता पार्टी बताया और कहा कि सरकार अमेरिका के सामने इतना नतमस्तक क्यों है? जब भी देश पर कोई कठिनाई आती है तो ये सरकार मौन क्यों हो जाती है. सरकार ने लोगों को लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की. सपा सांसद ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए एलपीजी संकट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ये समझना चाहिए कि जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए है. चाहे घरेलू सिलेंडर हो या कमर्शियल सिलेंडर हो. जिस तरह हवाई जहाज के टिकट के दाम बढ़ रहे है, जिस तरह मार्केट में सिलेंडर नहीं मिल रहे है. क्योंकि लगातार ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह लोग लाइनों में खड़े हुए है. चाहे वो गोरखपुर हो, लखनऊ हो या मैनपुरी हो.. पेट्रोल और सिलेंडर के लिए लोग लगातार लाइन में खड़े हुए है.डिंपल यादव ने कहा कि ये सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों को दिक्कतें आ रही है. लोग महंगाई का सामना कर रहे है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है. सरकार की विदेश नीति कैसी है कि जो अमेरिका के सामने नतमस्तक है. जहां इतना बड़ा ट्रेड डील आप अमेरिका के साथ साइन कर रहे है. जहां, हमारे आयात लगातार बढ़ाए जा रहे है और हमारे निर्यात घटेंगे तो कहीं न कहीं सरकार किसी भी तरह तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस डील से हमारे कृषि क्षेत्र पर इतना बड़ा नुकसान होने वाला है. आखिर सरकार क्यों अमेरिका के सामने नतमस्तक है. सरकार की कोई तैयारी क्यों नहीं है? ये सरकार प्रचार प्रसार तो बहुत करती है लेकिन जब कोई भी कठिनाई या कष्ट आता है तो ये सरकार मौन हो जाती है. ये भारतीय जनता पार्टी नहीं ये ब्लंडर जनता पार्टी है जो देश के लिए ब्लंडर साबित हो रही है.

एलपीजी संकट पर लोकसभा में विपक्ष ने नारेबाजी की

विपक्ष ने दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया

नई दिल्ली ।

संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन, शुक्रवार को भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ेंगे तो यही एक्शन होगा। लोकसभा में हंगामे का कारण पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक फिर से कार्यवाही स्थगित की गई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सरकार जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह तैयार रहने के लिए कदम उठा रही है। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वह गैर-जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में एलपीजी संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर, सूत्रों ने बताया कि टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के खिलाफ दोनों सदनों में प्रस्ताव दिया है।

इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन क्रैश

4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता; जंग में अब तक 11 अमेरिकी सैनिक मारे गए

तेहरान । अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूलिंग विमान गुरुवार को क्रैश हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत हो गई है, जबकि 2 अभी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। अधिकारियों के मुताबिक यह विमान एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय मिशन में दूसरा अमेरिकी टैंकर विमान भी शामिल था। हालांकि दूसरा विमान सुरक्षित रहा। अमेरिकी सेना ने साफ किया है कि यह हादसा किसी दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ।

हादसे के बाद ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इससे पहले 1 मार्च को कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जबकि इस महीने सऊदी अरब में हुए हमले में घायल एक सैनिक की बाद में मौत हो गई थी।

दावा- ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पैर काटना पड़ा

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में है। ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में चोट इतनी गहरी थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा और लिवर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां भारी सुरक्षा तैनात है। मुजतबा खामेनेई को उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद 9 मार्च को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हुई थी।